sold only to the poor and needy persons:—

(a) Sale of controlled cloth in the rural area may be restricted to small farmers having holdings upto 2 hectares (5 acres)

(b) In urban areas, sale of controlled cloth may be restricted to persons who do not pay income-tax.

राजभाषा कार्यान्वियन समिति की स्थापना

3330. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय/विभाग में राजभाषा कार्यान्वियन समिति की स्थापना की गई है,

(ख) यदि हां, तो 1977 में उसकी किन-किन तिथियों को बैठकें हुई तथा प्रत्येक बैठक में क्या-क्या निर्णय किये गये,

(ग) उनमें से कितने निर्णयों को पूरी तरह लागू किया गया है, और

(घ) जिन निर्णयों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है उनके बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ). जी, हां, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में शासकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग के बारे में सरकारी नीतियों और आदेशों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वियन समिति का पहले ही गठन किया जा चुका है। वर्ष 1977 में इसकी बैठक 28 अक्तूबर, 1977 को हुई थी, जिसके कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी–1832/78]।

इस बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रकृति से यह स्पष्ट है कि इनका क्रियान्वयन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा क्रियान्वयन की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने में समय लगेगा। तथापि संबंधित सभी को इस बैठक में लिये गये निर्णयों के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

हीरों और जवाहरात की तस्करी की जांच

3331. **श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी** :
चौधरी रामगोपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान साप्ताहिक पत्र 'पंचजन्य' दिनांक 4 सितम्बर, 1977 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें 60 लाख रुपये के हीरे जवाहरात की तस्करी का विवरण दिया गया है जिसमें बहुत से सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, और

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इस मामले की कोई जांच नहीं की है क्योंकि तस्करी में सरकारी अधिकारी शामिल थे और यदि हां, तो क्या सरकार अब इस मामले की जांच करेगी और यदि कोई जांच की गई थी तो उसका क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख). सरकार को इस खबर की जानकारी है। 19/20 अगस्त, 1976 को पालम हवाई अड्डे पर 58 लाख रुपये मूल्य के हीरे पकड़े गये थे। मामले में की गयी जांच से पता चला है कि हीरों का भारत से बाहर चोरी-छिपे निर्यात किये जाने का प्रयास किया जा रहा था। हीरों को जब्त कर लिया गया है। इस मामले में ग्रस्त व्यक्तियों के खिलाफ इस्तगासे की कार्यवाही

शुरू की गयी है। एक सीमाशुल्क अधिकारी के खिलाफ भी अलग से इस्तगा से की कार्यवाही शुरू की गयी है। कुछ और सी० शु० अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का विचार है।

Reduction in interests of Nationalised Banks to Small Trades and Entrepreneurs

3332 SHRI SHYAM SUNDAR GUPTA Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce the interest on loans given by nationalised banks to small traders and small entrepreneurs to enable them to improve their business, and

(b) if not the reasons thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL): (a) and (b). Loans upto specified amounts granted to small traders and entrepreneurs are already exempted from the Reserve Bank of India's directive on the minimum lending rate of 12 5 per cent as they form part of the neglected sector Accordingly, in deserving cases, banks do provide loans to such borrowers at rates lower than the minimum lending rate In other cases the maximum ceiling rate of 15 per cent recently fixed by the Reserve Bank of India is applicable. However, banks have been advised to pass the benefits of the abolition of interest tax and reduced rates of interest on deposits to their borrowers in the interest of economic development.

सोवियत रूस के आर्थिक तथा व्यापार मंडल द्वारा भारत में पूंजी लगाया जाना

3333. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 में देश के कुछ उद्योगों में सोवियत रूस के आर्थिक तथा व्यापार मंडल ने पूंजी लगाने का प्रस्ताव किया था, और

(ख) यदि हां, तो उसका सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बुल्लिकारउल्ला) : (क) और (ख) 1977 के दौरान, भारत स्थित कतिपय उद्योगों में पूंजी निवेश करने के लिए किसी सोवियत प्राधिकारी का कोई खास प्रस्ताव नहीं था। लेकिन, अप्रैल, 1977 में सोवियत सरकार ने भारत सरकार को 25 करोड़ रूबल का ऋण प्रस्तुत किया जिसका उपयोग लौह धातु कर्मक उद्योग के विकास के लिए रानीगंज तथा सिंगरौली क्षेत्रों में स्थित कोयला खनन परियोजनाओं के लिए तथा उन अन्य परियोजनाओं के लिए किया जाना था जिनके संबंध में परस्पर सहमति हो जाये। इस ऋण के उपयोग के संबंध में प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। अक्टूबर, 1977 में सोवियत सरकार आन्ध्र प्रदेश में एक एल्यूमीना संयंत्र का निर्माण करने में सहयोग देने के लिए सहमत हुई जिसके लिए प्रतिकरात्मक आधार पर वित्त व्यवस्था की जाएगी। इस प्रस्ताव पर भी आगे विचार किया जा रहा है।

Dilution of Foreign Equity holding by Foreign Companies under FERA

3334. SHRI M. KALYANASUNDARAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of foreign companies which have submitted the proposals for the dilution of their equity holdings in line with the provisions under the FERA;

(b) the number of companies which have not submitted yet/not agreed to do so; and